International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

ग्रामीण हरियाणा से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनः एक ऐतिहासिक अध्ययन

सन्तरो कुमारी
शोधार्थी, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर रोहतक
Sawitachopra9398@gmail.com, Registration No. – 23-BMU-7230

डॉ. राजबीर सिंह गुलिया
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक

सारांश
हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवम्बर 1966 को हुई। राज्य गठन के समय इसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना मुख्यतः ग्रामीण तथा कृषि–आधारित थी। हरित क्रांति, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण, सड़क एवं विद्युत सुविधाओं का विकास और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकटता ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ उद्योग, परिवहन, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इस बदलती आर्थिक संरचना ने ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर भूमिहीन श्रमिकों, छोटे किसानों, शिक्षित युवाओं और रोजगार की तलाश करने वाले परिवारों को शहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया। 1966 से 2000 तक ग्रामीण हरियाणा से शहरों की ओर प्रवासन केवल रोजगार की खोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने ग्रामीण समाज के पारिवारिक संबंधों, कृषि व्यवस्था, आय–स्रोतों, महिलाओं की भूमिका, शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं, उपभोग–व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता को भी प्रभावित किया। 1991 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 75.37 प्रतिशत थी, जबकि शहरी जनसंख्या लगभग 24.63 प्रतिशत थी। 1999–2000 के हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घट रहा था, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ रहा था। यही आर्थिक परिवर्तन ग्रामीण से शहरी प्रवासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। यह शोध–पत्र 1966 से 2000 तक की अवधि में ग्रामीण हरियाणा से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन के कारणों, स्वरूप, सामाजिक–आर्थिक प्रभावों और नीतिगत प्रयासों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
मुख्य शब्दः ग्रामीण हरियाणा, शहरी प्रवासन, नगरीकरण, हरित क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था।

प्रस्तावना
प्रवासन सामाजिक परिवर्तन की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अथवा परिवार आजीविका, शिक्षा, सुरक्षा, सुविधाओं अथवा बेहतर जीवन की आशा में अपने मूल निवास से अन्य स्थान की ओर जाते हैं। ग्रामीण से शहरी प्रवासन विशेष रूप से उस स्थिति में तीव्र

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

होता है, जब गाँवों में रोजगार के साधन सीमित होने लगते हैं और नगरों में उद्योग, व्यापार, निर्माण तथा सेवाओं के नए अवसर विकसित होते हैं। हरियाणा में 1966 से 2000 तक की अवधि इसी प्रकार के परिवर्तन की साक्षी रही। राज्य निर्माण के आरम्भिक समय में हरियाणा का अधिकांश समाज गाँवों में निवास करता था। कृषि, पशुपालन और उनसे संबंधित कार्य ग्रामीण जीवन का आर्थिक आधार थे। हरित क्रांति के बाद गेहूँ और धान की उच्च उत्पादक किस्मों, रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई साधनों और कृषि मशीनरी के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इससे एक ओर ग्रामीण समृद्धि का नया वर्ग उत्पन्न हुआ, वहीं दूसरी ओर मशीनों के बढ़ते प्रयोग ने परम्परागत श्रम की आवश्यकता को सीमित किया। जिन परिवारों के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी, अथवा जिनकी आय कृषि से स्थिर नहीं हो पा रही थी, उनके लिए शहरों की ओर जाना रोजगार प्राप्ति का विकल्प बनता गया।

हरियाणा की भौगोलिक स्थिति ने भी प्रवासन को प्रभावित किया। दिल्ली से जुड़ा गुरुग्राम क्षेत्र, फरीदाबाद का औद्योगिक विस्तार, पानीपत का वस्त्र एवं व्यापारिक विकास, यमुनानगर का औद्योगिक आधार, रोहतक, सोनीपत और करनाल जैसे उभरते नगर ग्रामीण जनसंख्या के लिए आकर्षण केन्द्र बने। इस प्रकार 1966 से 2000 तक हरियाणा में ग्रामीण से शहरी प्रवासन कृषि समाज से बदलती हुई औद्योगिक तथा सेवा–प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण का महत्त्वपूर्ण संकेतक बन गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हरियाणा का गठन 1 नवम्बर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप हुआ। राज्य निर्माण के समय सात जिले थे, जिनमें अम्बाला, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, हिसार और जींद सम्मिलित थे। बाद के दशकों में प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत भिवानी और सोनीपत 1972 में, कुरुक्षेत्र 1973 में, सिरसा 1975 में, फरीदाबाद 1979 में, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी 1989 में, पंचकूला 1995 में तथा झज्जर और फतेहाबाद 1997 में अलग जिलों के रूप में स्थापित हुए। यह प्रशासनिक विस्तार जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय विकास और नगरीय केन्द्रों के बढ़ते महत्त्व का सूचक था। राज्य के आरम्भिक विकास की मुख्य शक्ति कृषि थी। नहर सिंचाई, नलकूप, ग्रामीण विद्युतीकरण, मंडी व्यवस्था, उच्च उपज वाले बीज और कृषि ऋण सुविधाओं ने हरियाणा को हरित क्रांति का प्रमुख क्षेत्र बनाया। किन्तु कृषि का यह विकास सभी वर्गों में समान रूप से वितरित नहीं हुआ। बड़े और मध्यम किसान आधुनिक कृषि साधनों का लाभ अधिक उठा सके, जबकि छोटे किसान, सीमांत किसान और भूमिहीन श्रमिक कृषि कार्य के सीमित अवसरों तथा बढ़ती आर्थिक आवश्यकताओं के कारण वैकल्पिक रोजगार की ओर उन्मुख हुए। 1990 के दशक तक राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 1999–2000 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा 1993–94 के 42.8 प्रतिशत से घटकर 1998–99 में 35.5 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 18.9 प्रतिशत से बढ़कर 21.3 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 32.9

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रतिशत से बढ़कर 38.2 प्रतिशत हो गया। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कृषि के साथ–साथ उद्योग तथा सेवाएँ रोजगार और आय के नए केन्द्र बन रही थीं।

हरियाणा में ग्रामीण और शहरी संरचना का परिवर्तन

हरियाणा राज्य के गठन के बाद आरम्भिक दशकों में ग्रामीण समाज का प्रभुत्व बना रहा। कृषि उत्पादन, पशुपालन और ग्रामीण बाजार अधिकांश परिवारों की आजीविका के आधार थे। किन्तु शहरी केन्द्रों का महत्त्व धीरे–धीरे बढ़ने लगा। औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक मंडियों, शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, परिवहन सेवाओं और निर्माण गतिविधियों के विस्तार ने नगरों को रोजगार और सुविधा के केन्द्रों में परिवर्तित किया। 1991 की जनगणना में हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या 1,24,08,904 और शहरी जनसंख्या 40,54,744 दर्ज की गई। इस समय ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 75.37 प्रतिशत थी।

इसका अर्थ है कि राज्य अब भी मूलतः ग्रामीण था, किन्तु लगभग एक चौथाई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहने लगी थी। इस शहरी हिस्से का विस्तार केवल प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं था, बल्कि रोजगार, व्यापार, उद्योग, प्रशासनिक पुनर्गठन और ग्रामीण जनसंख्या की शहरी अवसरों की ओर बढ़ती गतिशीलता से भी जुड़ा था। इस अवधि में फरीदाबाद औद्योगिक गतिविधियों के कारण विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हुआ। गुड़गांव में दिल्ली की निकटता, सड़क संपर्क, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और निजी गतिविधियों के विस्तार ने शहरी आकर्षण को बढ़ाया। पानीपत में कपड़ा उद्योग और व्यापार, यमुनानगर में लकड़ी, कागज तथा औद्योगिक इकाइयाँ, करनाल और रोहतक में शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक अवसर ग्रामीण युवाओं के लिए आकर्षण का कारण बने।

ग्रामीण से शहरी प्रवासन के प्रमुख कारण

1. कृषि में परिवर्तन और श्रम की बदलती आवश्यकता

हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति ने गहरा प्रभाव डाला। वर्ष 1966–67 में गेहूँ के अंतर्गत क्षेत्र 7.43 लाख हेक्टेयर और धान के अंतर्गत क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टेयर था। वर्ष 1998–99 तक गेहूँ का क्षेत्र बढ़कर 21.88 लाख हेक्टेयर और धान का क्षेत्र 10.83 लाख हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार कुल खाद्यान्न उत्पादन 1970–71 के 47.71 लाख टन से बढ़कर 1998–99 में 121.23 लाख टन हो गया। उत्पादन वृद्धि ने ग्रामीण आय में विस्तार किया, किन्तु इसके साथ कृषि का यंत्रीकरण भी बढ़ा। ट्रैक्टर, थ्रेशर, सिंचाई पम्प और अन्य मशीनों ने कृषि कार्य को अधिक उत्पादक बनाया, परन्तु अनेक प्रकार के मौसमी श्रम की आवश्यकता कम कर दी। भूमिहीन श्रमिकों और छोटे किसानों के लिए कृषि से पूरे वर्ष पर्याप्त आय प्राप्त करना कठिन होता गया। ऐसे लोगों ने निकटवर्ती कस्बों और शहरों में मजदूरी, निर्माण, उद्योग, परिवहन और छोटे व्यापार को अपनाना आरम्भ किया।

2. भूमि का विभाजन और छोटे किसानों की कठिनाइयाँ

परिवारों के विस्तार और उत्तराधिकार के कारण कृषि भूमि छोटे–छोटे भागों में विभाजित होती गई। सीमित जोत पर आधुनिक कृषि लागत, बीज, उर्वरक, सिंचाई और मशीनों का

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

खर्च वहन करना अनेक परिवारों के लिए कठिन था। कृषि से प्राप्त आय परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, आवास और दैनिक उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। इसलिए ग्रामीण परिवारों ने आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहरी रोजगार को अपनाया।

3. औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का विस्तार

1990 के दशक में हरियाणा में उद्योग और सेवा क्षेत्रों का महत्त्व बढ़ा। 1998–99 में विनिर्माण क्षेत्र ने 6.3 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र ने 7.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित थीं। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण ने स्वयं स्वीकार किया कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से विनिर्माण और सेवाओं की ओर बढ़ रही थी। शहरी क्षेत्रों में कारखानों, दुकानों, कार्यालयों, मंडियों, परिवहन प्रतिष्ठानों, निजी सेवाओं और निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर विकसित हुए। ग्रामीण युवाओं के लिए शहरों में दैनिक मजदूरी, नियमित वेतन और नकद आय की संभावना गाँवों की अनिश्चित कृषि आय की तुलना में अधिक आकर्षक प्रतीत हुई।

4. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रभाव

हरियाणा की शहरी वृद्धि में दिल्ली की निकटता का विशेष महत्त्व रहा। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में दिल्ली से आर्थिक संपर्क ने उद्योग, निर्माण, आवागमन और निजी रोजगार को बढ़ावा दिया। अनेक ग्रामीण व्यक्ति स्थायी रूप से शहरों में बसने के बजाय प्रतिदिन अथवा अस्थायी अवधि के लिए काम करने जाने लगे। इस प्रकार प्रवासन का स्वरूप केवल स्थायी निवास–परिवर्तन नहीं था, बल्कि दैनिक आवागमन, मौसमी प्रवासन और अर्ध–स्थायी शहरी बसावट के रूप में भी विकसित हुआ।

5. शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं की इच्छा

1966 से 2000 तक ग्रामीण समाज में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। सरकारी नौकरियों, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक रोजगार और शहरी जीवन की बढ़ती प्रतिष्ठा ने परिवारों को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए नगरों से जोड़ना आरम्भ किया। शहरों में महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, अस्पताल, बैंक, परिवहन और संचार सुविधाएँ अधिक उपलब्ध थीं। इस कारण अनेक परिवारों के लिए प्रवासन केवल आय अर्जन नहीं, बल्कि सामाजिक उन्नति और बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़ा निर्णय बन गया।

ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर प्रवासन का प्रभाव

ग्रामीण से शहरी प्रवासन ने ग्रामीण परिवारों की आय संरचना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया। पूर्व में परिवार की आय मुख्यतः फसल, पशुपालन और कृषि मजदूरी पर निर्भर रहती थी। शहरों में रोजगार प्राप्त करने वाले सदस्यों ने वेतन अथवा मजदूरी के रूप में नकद आय भेजनी प्रारम्भ की। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक निर्भरता केवल खेती पर सीमित नहीं रही। प्रवासी आय का उपयोग प्रायः मकान निर्माण, बच्चों की पढ़ाई, विवाह खर्च, कृषि उपकरण, पशुधन, सिंचाई साधनों और घरेलू वस्तुओं की खरीद में किया गया। ग्रामीण घरों

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

में पक्के निर्माण, बिजली के उपकरण, वाहन, बेहतर वस्त्र और उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग बढ़ने लगा। इस प्रकार प्रवासन ने ग्रामीण जीवन में बाजार आधारित उपभोग–संस्कृति को विस्तार दिया। साथ ही, प्रवासन ने आर्थिक असमानता को भी प्रभावित किया। जिन परिवारों के सदस्य शहरों में स्थिर नौकरी अथवा लाभकारी व्यवसाय प्राप्त कर सके, उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरी। इसके विपरीत दिहाड़ी मजदूरी, अस्थायी निर्माण कार्य अथवा कम वेतन वाली सेवाओं में लगे प्रवासी परिवारों को अनिश्चित आय और शहरी जीवन की अधिक लागत का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रवासन से प्राप्त लाभ सभी ग्रामीण परिवारों में समान नहीं था।

कृषि व्यवस्था और ग्रामीण श्रम पर प्रभाव

शहरों की ओर कार्यशील जनसंख्या के जाने से ग्रामीण कृषि व्यवस्था में परिवर्तन आया। छोटे किसानों के परिवारों में युवा सदस्य गैर–कृषि रोजगार से जुड़ने लगे, जिसके कारण खेती का कार्य बुजुर्गों, महिलाओं अथवा किराये के श्रमिकों पर अधिक निर्भर होने लगा। कुछ परिवारों ने अपनी भूमि को बटाई अथवा ठेके पर देना आरम्भ किया, जबकि कुछ ने शहरी आय के माध्यम से खेती में मशीनों और आधुनिक संसाधनों का निवेश बढ़ाया। प्रवासन और कृषि यंत्रीकरण एक–दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएँ बनीं। कृषि मजदूरों का शहरों की ओर जाना मशीनों की आवश्यकता को बढ़ाता था, जबकि मशीनों का प्रयोग ग्रामीण श्रमिकों को वैकल्पिक आजीविका खोजने के लिए प्रेरित करता था। इस कारण ग्रामीण हरियाणा में परम्परागत कृषि श्रम संबंध धीरे–धीरे बदलने लगे। 1999–2000 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि अब भी राज्य की 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार थी, किन्तु कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की संभावना सीमित हो चुकी थी। सर्वेक्षण ने यह भी उल्लेख किया कि 1984–85 के बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल क्षेत्रफल के लगभग 81 से 83 प्रतिशत के बीच बना रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए केवल भूमि विस्तार पर निर्भर रहना संभव नहीं था।

सामाजिक संरचना में परिवर्तन

1. परिवार व्यवस्था में बदलाव

ग्रामीण से शहरी प्रवासन ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया। प्रारम्भिक अवस्था में परिवार का एक पुरुष सदस्य अकेला शहर जाकर काम करता था और आय गाँव भेजता था। बाद में रोजगार स्थिर होने पर पत्नी और बच्चों को भी शहर ले जाने की प्रवृत्ति विकसित हुई। इससे गाँव में वृद्ध माता–पिता तथा सीमित सदस्य रह जाते थे। इस परिवर्तन ने पारिवारिक सहयोग, सम्पत्ति प्रबंधन, बुजुर्गों की देखभाल और सामाजिक उत्तरदायित्वों के स्वरूप को प्रभावित किया।

2. शिक्षा के प्रति नई आकांक्षा

शहरी संपर्क से ग्रामीण परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। प्रवासी परिवारों ने अनुभव किया कि सरकारी नौकरी, कार्यालयी कार्य, तकनीकी रोजगार और व्यापारिक उन्नति के

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

लिए शिक्षा आवश्यक है। फलस्वरूप बच्चों की पढ़ाई पर खर्च बढ़ा, निजी विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ और ग्रामीण युवाओं में नौकरी तथा पेशागत गतिशीलता की इच्छा मजबूत हुई।

3. महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन

पुरुष सदस्यों के शहरों की ओर जाने के कारण गाँव में महिलाओं की जिम्मेदारियाँ बढ़ीं। वे घरेलू कार्यों के साथ पशुपालन, खेतों की निगरानी, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक संबंधों और आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय हुईं। कुछ महिलाओं ने दूध उत्पादन, सिलाई, घरेलू उत्पादन और स्वयं सहायता आधारित गतिविधियों से भी जुड़ना आरम्भ किया। 1999–2000 के आर्थिक सर्वेक्षण में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गाँव स्तर पर महिला मंडलों के गठन का उल्लेख किया गया है। इसी अवधि में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएँ भी चलाई जा रही थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि आर्थिक परिवर्तन के साथ ग्रामीण महिला की सामाजिक भूमिका को नीतिगत स्तर पर भी महत्त्व मिलने लगा था।

4. सामाजिक संबंधों और जीवन–शैली में परिवर्तन

शहरी जीवन के संपर्क में आने वाले प्रवासी ग्रामीण लोगों की भाषा, रहन–सहन, वस्त्र, भोजन, आवास और उपभोग संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव आया। शहरों में जाति और बिरादरी से बाहर के लोगों के साथ काम करने से सामाजिक अनुभव विस्तृत हुआ। यद्यपि विवाह, सम्पत्ति और सामुदायिक पहचान के मामलों में परम्परागत संरचनाएँ बनी रहीं, फिर भी रोजगार और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता के नए अवसर विकसित हुए।

शहरी क्षेत्रों पर प्रवासन का प्रभाव

ग्रामीण प्रवासी हरियाणा के नगरों की आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्त्वपूर्ण श्रमशक्ति बने। फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर और अन्य कस्बों में कारखानों, निर्माण स्थलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, परिवहन सेवाओं, घरेलू कार्यों और छोटे उद्योगों में ग्रामीण श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी। शहरों का विस्तार ग्रामीण श्रम के बिना संभव नहीं था। किन्तु तीव्र शहरी वृद्धि के साथ अनेक समस्याएँ भी सामने आईं। कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षित तथा सस्ते आवास की कमी थी। अनेक लोग अनाधिकृत बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के निकट छोटे किराये के कमरों अथवा अपर्याप्त सुविधाओं वाले स्थानों में रहने लगे। जल, स्वच्छता, परिवहन, स्वास्थ्य और विद्यालयों पर दबाव बढ़ा।

अस्थायी रोजगार के कारण सामाजिक सुरक्षा, नियमित आय और कार्यस्थल सुरक्षा की स्थिति भी कमजोर रही। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने वाले व्यक्तियों में सभी को आर्थिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुछ श्रमिकों के लिए शहर केवल मजदूरी का स्थान रहा, जहाँ रहने की लागत अधिक थी और आय अनिश्चित थी। इस प्रकार प्रवासन ने अवसर प्रदान किए, परन्तु सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

सरकारी योजनाएँ और रोजगार संबंधी प्रयास

1966 से 2000 तक हरियाणा सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी तथा शहरी गरीबों की सहायता के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की गईं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना तथा गरीब वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। 1999–2000 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1998–99 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 6.80 लाख परिवारों की पहचान की गई थी। वर्ष 1999–2000 में इस कार्यक्रम का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया। 31 दिसम्बर 1999 तक इस योजना के अंतर्गत 4,026 लाभार्थियों को सहायता दी गई और 903.94 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। ग्रामीण रोजगार के लिए जवाहर रोजगार समृद्धि योजना के अंतर्गत भी 31 दिसम्बर 1999 तक 11.83 लाख मानव–दिवस का रोजगार उत्पन्न किया गया।

शहरी गरीबों के लिए नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर तथा प्रधानमंत्री शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को 1 दिसम्बर 1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया। दिसम्बर 1999 तक इस योजना के अंतर्गत 1,680 लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई गई। यह तथ्य दर्शाता है कि अध्ययन अवधि के अंतिम वर्षों में सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन की समस्याओं को संबोधित करने का प्रयास कर रही थी। इन योजनाओं के बावजूद ग्रामीण से शहरी प्रवासन समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि प्रवासन केवल गरीबी का परिणाम नहीं था। यह बेहतर आय, शिक्षा, आधुनिक जीवन–सुविधाओं और सामाजिक उन्नति की आकांक्षा से भी संचालित था।

ग्रामीण से शहरी प्रवासन के सकारात्मक प्रभाव

1966 से 2000 तक प्रवासन ने ग्रामीण हरियाणा में अनेक सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न किए। सबसे पहले, इसने कृषि पर पूर्ण निर्भरता को कम करके आय के नए स्रोत विकसित किए। शहरों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा भेजी गई धनराशि ने परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। दूसरा, प्रवासन ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, आवास सुधार और उपभोक्ता सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाई। तीसरा, ग्रामीण युवाओं को उद्योग, परिवहन, तकनीकी कार्य, सरकारी कार्यालय और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिला। प्रवासन ने ग्रामीण समाज में नई आकांक्षाओं को भी जन्म दिया। शिक्षा, कौशल, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्त्व बढ़ा। महिलाओं की घरेलू तथा आर्थिक भूमिका में विस्तार हुआ। शहरी संपर्क ने ग्रामीण परिवारों को नई तकनीक, संचार साधनों और आधुनिक बाजार व्यवस्था से जोड़ा। इस प्रकार प्रवासन सामाजिक गतिशीलता का माध्यम भी बना।

प्रवासन से उत्पन्न समस्याएँ

प्रवासन के सकारात्मक प्रभावों के साथ अनेक समस्याएँ भी दिखाई देती हैं। ग्रामीण परिवारों में युवा सदस्यों की अनुपस्थिति से कृषि प्रबंधन, बुजुर्गों की देखभाल और पारिवारिक सहयोग

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रभावित हुआ। महिलाओं पर घरेलू और कृषि संबंधी जिम्मेदारियाँ बढ़ीं। छोटे किसानों के लिए कृषि कार्य को निरंतर बनाए रखना कठिन हुआ। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को निम्न मजदूरी, अस्थायी रोजगार, भीड़भाड़ वाले आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ा। शहरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण सार्वजनिक सुविधाओं पर दबाव बढ़ा। अनेक प्रवासी आर्थिक अवसरों की तलाश में शहर पहुँचे, किन्तु वे स्थिर और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता भी बढ़ी। स्थिर शहरी रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़े, जबकि गरीब तथा असंगठित श्रम में लगे परिवारों की स्थिति में सीमित सुधार हुआ।

निष्कर्ष

ग्रामीण हरियाणा से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का इतिहास राज्य के विकास की बदलती दिशा को समझने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। 1966 में गठित हरियाणा मुख्यतः ग्रामीण और कृषि–प्रधान राज्य था। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, किन्तु कृषि यंत्रीकरण, भूमि विभाजन, सीमित रोजगार और बढ़ती सामाजिक आकांक्षाओं ने अनेक ग्रामीण परिवारों को वैकल्पिक अवसरों की तलाश के लिए प्रेरित किया। फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, करनाल और सोनीपत जैसे शहरी केन्द्र उद्योग, व्यापार, शिक्षा, परिवहन और सेवाओं के कारण ग्रामीण जनसंख्या के आकर्षण क्षेत्र बने। 1990 के दशक तक राज्य की आर्थिक संरचना में कृषि का सापेक्ष हिस्सा घटने और विनिर्माण तथा सेवाओं का योगदान बढ़ने से प्रवासन की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हुई।

प्रवासन ने ग्रामीण परिवारों के लिए आय, शिक्षा और आधुनिक जीवन–सुविधाओं के अवसर प्रदान किए, परन्तु इसके कारण कृषि श्रम संबंधों, परिवार व्यवस्था, महिलाओं की जिम्मेदारियों और शहरी जीवन की समस्याओं में भी परिवर्तन आया। इसलिए इस अवधि में प्रवासन को न तो केवल ग्रामीण संकट के रूप में देखा जा सकता है और न ही केवल विकास की उपलब्धि के रूप में। यह अवसर और चुनौती, दोनों से जुड़ी प्रक्रिया थी। अंततः कहा जा सकता है कि 1966 से 2000 तक ग्रामीण हरियाणा से शहरों की ओर प्रवासन ने राज्य को कृषि–प्रधान ग्रामीण समाज से अधिक गतिशील, बाजार–आधारित और नगरीय प्रभाव वाले समाज की ओर अग्रसर किया। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने हरियाणा की सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन और विकास की दिशा पर स्थायी प्रभाव डाला।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार, जनगणना आयुक्त कार्यालय. (1991). भारत की जनगणना 1991, श्रृंखला 8: हरियाणा, अनंतिम जनसंख्या योग. नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड. (2009). दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रवासन अध्ययन. नई दिल्ली: भारत सरकार।

3. राहुल. (2021). हरियाणा में प्रवासनः आगमन, निर्गमन और कारण. हेल्थ एंड पॉपुलेशनः पर्सपेक्टिव्स एंड इश्यूज, 44(4), पृ० 188–198.
4. राहुल. (2022). हरियाणा में प्रवासन के बदलते स्वरूप. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च – ग्रंथालयाह, 10(9), पृ० 143–152.
5. शर्मा, जयश्री. (2014). हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में प्रवासियों की संरचना. द इंटरनेशनल जर्नल्स रिसर्च जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, 3(9), जुलाई 2014.
6. स्केल्डन, रोनाल्ड. (1986). 1970 के दशक में भारत में प्रवासन के स्वरूप. पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू, 12(4), पृ० 759–779.
7. जनगणना संचालन निदेशालय, हरियाणा. (1993). भारत की जनगणना 1991: हरियाणा, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या वितरण. चंडीगढ़: भारत सरकार।
8. आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा सरकार. (2000). हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 1999–2000. पंचकूलाः हरियाणा सरकार।
9. आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्य विभाग, हरियाणा सरकार. (2025). हरियाणा का सांख्यिकीय सार–संग्रह 2023–24. पंचकूलाः हरियाणा सरकार।